

दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के साथ खड़ा होना जरूरी: राजीव दत्ता

यूनाइटेड प्रेस क्लब की सद्भावना सभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी ने पत्रकारों के योगदान को किया याद, परिवारों की मदद को बताया सामाजिक जिम्मेदारी

समर न्यूज | लुधियाना

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। वे जोखिम और विषम परिस्थितियों के बावजूद घटनास्थल पर पहुंचकर सच्चाई समाज के सामने लाते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कई पत्रकारों ने प्राण गंवाए हैं। ऐसे में दिवंगत पत्रकारों के परिवारों की सुध लेना समाज की जिम्मेदारी है। दत्ता शुक्रवार को लुधियाना के गुरु नानक देव भवन में यूनाइटेड प्रेस क्लब की ओर से दिवंगत पत्रकारों की स्मृति में आयोजित धार्मिक सद्भावना सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार पत्रकारों के निधन के बाद उनके परिवार अकेले पड़ जाते हैं। क्लब की ओर से ऐसे परिवारों को आर्थिक सहयोग और सामाजिक संबल देने की पहल सराहनीय है।

■ **परिवारों को भरोसा देना जरूरी:** दत्ता ने एक दिवंगत पत्रकार के परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि पत्रकार के जीवित रहते घर में लोगों का आना-जाना रहता था, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं बचा। उन्होंने कहा कि ऐसे



परिवारों को यह एहसास कराना जरूरी है कि वे अकेले नहीं हैं। ■ **धार्मिक सद्भाव का संदेश:** सभा में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, संतों, जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने दिवंगत पत्रकारों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। क्लब अध्यक्ष अशदीप सिंह समर ने कहा कि वर्ष 2014 में स्थापित संस्था पत्रकारों के कल्याण, जरूरतमंद परिवारों की सहायता और सामाजिक एकता के लिए काम कर रही है।



अरोड़ा बोले, आप को मिलेगा जनता के काम का इनाम

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने दोबारा सत्ता में लौटने का दावा किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल में चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के साथ कई ऐसे काम भी किए हैं, जिनकी पहले घोषणा नहीं की गई थी।

उनके मुताबिक, सरकार के कामकाज को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल है और पार्टी को इसका लाभ आगामी चुनाव में मिलेगा। अरोड़ा ने यह बात एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने सरकार के कार्यकाल, चुनावी संभावनाओं और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर अपनी बात रखी। उनका दावा है कि आप सरकार ने अपनी पांच प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। हालांकि, इन दावों का स्वतंत्र आकलन करने



के लिए प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन और उसके लाभार्थियों से जुड़े आंकड़ों को देखना जरूरी है। पंजाब में नशे की समस्या और गैंगस्टर गतिविधियों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अरोड़ा ने आरोप लगाया कि जेलों में बंद गैंगस्टर बाहर अपने नेटवर्क के जरिए आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उन्होंने साबरमती जेल में बंद गैंगस्टरों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा और बंदरगाहों से जुड़े मामलों में केंद्र की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्यों के रास्तों से होने वाली तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने धार्मिक स्थलों पर माथा टेककर एकजुटता का दिया संदेश

पंजाबियत को मजबूत करना चाहती है कांग्रेस: परगट सिंह

समर न्यूज | अमृतसर

पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नफरत और टकराव की राजनीति में विश्वास नहीं करती। पार्टी भारतीय संविधान के मूल्यों और पंजाबियत की भावना को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पंजाब की खुशहाली, सामाजिक सद्भाव और विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

उनके साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने भी राज्य की बेहदरी और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देने की बात कही। परगट सिंह और सचिन पायलट ने आठ अक्टूबर को अमृतसर स्थित श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका। इस दौरान कांग्रेस के कई मौजूदा और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तथा पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। परगट सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर जाने का उद्देश्य राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि ईश्वर का आभार जताना



और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करना था। दोनों नेताओं के इस दौर के वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। परगट सिंह ने कहा कि पार्टी में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए योगदान देने की गुंजाइश है। उन्होंने खुद को टीम का हिस्सा बताते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस का नेतृत्व सामूहिक जिम्मेदारी है और लक्ष्य राज्य की बेहदरी होना चाहिए।

■ **नशा और भ्रष्टाचार बड़ी चुनौती:** सचिन पायलट ने पंजाब के सामने नशे की समस्या और भ्रष्टाचार को प्रमुख चुनौतियां बतायीं। उन्होंने कहा कि राज्य की समृद्धि बहाल करने, विकास को गति देने और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य तैयार करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

■ **आगे की रणनीति:** परगट सिंह दो अक्टूबर को पंजाब प्रदेश

वारिस पंजाब दे ने फूंकवा चुनावी बिगुल, पंथक राजनीति पर जोर

समर न्यूज | पटियाला

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़े इस संगठन ने पंथक राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने के उद्देश्य से पटियाला जिले के भादसों में जनसभा की। संगठन के नेताओं ने सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों के साथ पंजाब में नशे, गैंगस्टरों की वसूली और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई। इस पहल को शिरोमणि अकाली दल (बादल) के पारंपरिक पंथक जनाधार में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। सभा का आयोजन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्य सतविंदर सिंह टोहरा ने किया। इसमें संगठन के नेताओं और समर्थकों ने भाग लिया। नेताओं ने कहा कि पंजाब और सिख समुदाय के हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक विकल्पों



पर विचार करने की जरूरत है। लुधियाना जिले के दाखा से विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने आरोप लगाया कि एसजीपीसी पर पंथक हितों के विपरीत काम करने वाली ताकतों का प्रभाव बढ़ा है। उन्होंने इसे सिख समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए संस्थान के कामकाज में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। ये आरोप संगठन के नेताओं के हैं, एसजीपीसी के कामकाज को लेकर उनके दावों पर स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। अमृतपाल सिंह के पिता और संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष तरसेम सिंह ने कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ों, नशे से युवाओं की मौत और गैंगस्टरों की ओर से वसूली की घटनाओं का मुद्दा उठाया।

शिअद ही पंजाब, पंजाबियों का सच्चा प्रतिनिधि: सुखबीर

समर न्यूज | पटियाला

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब और यहां के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी के 'पंजाब बचाओ' अभियान के तहत उन्होंने लेहरा गागा और खनौरी में जनसभाएं कीं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। साथ ही, आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार, नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा।

सुखबीर बादल ने घोषणा की कि यदि अकाली दल सत्ता में लौटता है तो राज्य के सभी विद्यार्थियों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने निजी स्कूलों और कॉलेजों में भी गरीब परिवारों के कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को



प्रवेश दिलाने की योजना का प्रस्ताव रखा। उनके मुताबिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। अकाली दल अध्यक्ष ने प्रत्येक परिवार को सालाना 25 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार बनने पर पहले बंद या सीमित की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं को दोबारा शुरू करेगी और जरूरत

के अनुसार उनका दायरा बढ़ाएगी। उन्होंने गेहूं वितरण योजना के तहत प्रति परिवार 10 किलोग्राम के बजाय 50 किलोग्राम गेहूं देने, शगुन योजना की सहायता बढ़ाकर एक लाख रुपये करने और बुजुर्गों की पेंशन 3,100 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। ■ **आप सरकार पर आरोप:** सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है और नशे की समस्या तथा कानून-

व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि अकाली दल ने अपने पिछले कार्यकाल में नए ताप बिजली संयंत्र स्थापित कर पंजाब को बिजली की जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था और सत्ता में लौटने पर विकास की गति फिर तेज की जाएगी। ■ **चुनावी अभियान का विस्तार:** अकाली दल ने 2027 के चुनाव के लिए 'पंजाब बचाओ' अभियान के तहत घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं और सुझाव जुटाने की मुहिम भी शुरू की है। पार्टी का कहना है कि इन सुझावों के आधार पर चुनावी घोषणापत्र तैयार किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नशे और सामाजिक सुरक्षा पर किए गए वादे इस अभियान के प्रमुख हिस्से हैं। इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवस्था को लेकर विस्तृत योजना सामने आने के बाद ही प्रभाव का आकलन किया जा सकेगा।

पंजाब में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंटा गया: भाजपा

एजेंसी | नई दिल्ली

पंजाब में नगर निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया गया। भाजपा को यह प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आई है, जिसमें पटियाला के 28 और मोगा के 22 सहित कुल 50 वार्डों में नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अदालत का फैसला पंजाब में चुनावी प्रक्रिया के दौरान विपक्षी और निर्दलीय उम्मीदवारों को कथित तौर पर नामांकन दाखिल करने से रोकने, नामांकन पत्र फाड़ने, धमकियां देने और हिंसा की शिकायतों की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में



विफल रही है। भाजपा ने संबंधित अधिकारियों और आम आदमी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग भी की, जिनकी भूमिका जांच में सामने आए। मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर की अध्यक्षता वाले तथ्य-जांच आयोग की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण रही। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करते हुए संबंधित 50

वार्डों में दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, पुनः चुनाव की पूरी प्रक्रिया छह सप्ताह के भीतर पूरी की जानी है। इन वार्डों में पहले चुनाव दिसंबर 2024 में हुए थे। अब दोबारा मतदान कराने के आदेश ने राज्य की चुनावी व्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है। ■ **उम्मीदवारों की सुरक्षा की मांग:** भाजपा ने आगामी चुनावों में उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित

करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की धमकी, हिंसा या दबाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने को कहा है। हालांकि, भाजपा की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोपों को अदालत के आदेश और जांच में सामने आए तथ्यों से अलग समझना जरूरी है। ■ **आप ने भाजपा पर लगाए आरोप:** दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने हाल के दिनों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि वह किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह पंजाब में दोनों दलों के बीच टकराव बढ़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नगर निकाय चुनावों का विवाद राज्य की राजनीति में अहम मुद्दा बन सकता है।